दिनांक २२ मई २०१३ को १०:३० बजे नगड़ी, राँची में राज्यस्तरीय जलछाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची में आफिसर्स हॉस्टल, कृषक छात्रावास का उद्घाटन एवं सब्जी बीज प्रसंस्करण इकाई ग्राम–तिलकसुति प्रखण्ड– ईटकी के अनावरण कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्य में विकास को गति देने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में खेती/पैदावार व किसानों के हित को देखते हुए कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा अनूठी पहल करते हुए इस प्रशिक्षण केन्द्र में कृषक छात्रावास और सब्जी बीज प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया गया है।

आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य को कुदरत ने खूब नेमतें बख्शी है, देश की ४० फीसदी से अधिक खनिज सम्पदा सूबे में मौजूद हैं, लेकिन हमारा झारखण्ड राज्य मूलतः कृषि प्रधान सूबा है। राज्य की लगभग ७० प्रतिशत आबादी की आजीविका खेती–बारी से जुड़ी हुई है। अतः किसानों के विकास से जुड़े हर पहलू की ओर हमारे द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

दोस्तों ! इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि राज्य में औसतन अच्छी बारिश १२००–१४०० मी०मी० होने के बावजूद किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, पठारी इलाका होने के कारण पानी का बहाव हो जाता है। साथ ही मिट्टी के कटाव से भू–क्षरण की अनेक समस्यायें आ जाती हैं। खेती के लिए पानी की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण मानसून की अनिश्चितता भी है। अतः कृषि हित में जल संग्रहण बेहद उपयोगी है, इससे जल स्तर भी हमें अपने अनुकूल देखने को मिलता है। इसलिए मैं जल संग्रहण/जल छाजन करने हेतु किसानों को इसके प्रति जागरूक होने के लिए कहता हूँ, कृषि विभाग

तथा जल छाजन से जुड़े अन्य विभाग एवं स्वयंसेवी संस्था भी कृषकों में भूमि एवं जल संरक्षण हेतु जागरूकता लाने का कार्य करे।

मेरा मानना है कि कृषि पैदावार को बढ़ाने में कृषकों को नयी तकनीकों को भी अपनाना चाहिए, इस हेतु ससमय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाय। मुझे खुशी है कि कृषि विभाग द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए भूमि संरक्षण निदेशालय अन्तर्गत कृषकों को कृषि कार्य में दक्षता एवं भूमि संरक्षण की महत्ता पर आधारित आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय जल छाजन प्रशिक्षण केन्द्र, नगड़ी, राँची के परिसर में इस नव निर्मित छात्रावास में प्रति वर्ष लगभग दस हजार किसानों को ट्रेनिंग दी जायेगी। भूमि संरक्षण निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत "Jharkhand Agriculture and Social Management Institute" (JASMIN) का निबंधन करा कर स्वायत संस्था का गठन कर लिया गया है, जिसके जरिये Training Institute को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हम पूरा लाभ उठायें, ताकि दलहन के पैदावार में और बढ़ोतरी हो सके। हालांकि किसानों के बेहतर प्रयास के कारण हमारे सूबे को इस क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। किसान भाइयों राज्य के हर जिले में ६००० हजार एम०टी० के एक-एक एवं १००० हजार एम०टी० के दो-दो गोदाम तथा प्रत्येक प्रखण्ड में १०० एम०टी० के दो-दो गोदाम तैयार किये जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादों के भण्डारण, मूल्य निर्धारण एवं वितरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं पूर्वी राज्यों में द्वितीय हरित क्रांति विस्तार योजना (BGREI) अन्तर्गत बिरसा पक्का चेक डैम, लिफ्ट् सिंचाई व्यवस्था की समेकित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत पुराने बड़े तालाबों का मशीन द्वारा गहरीकरण कराया जा रहा है। योजनायें पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित करायी जा रही है, जिससे लगभग ४० हजार हेक्टेयर में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। पंचायतें योजनाओं के निर्माण एवं किसानों की सहभागिता से संचालन में बेहतर साबित हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वी राज्यों में द्वितीय हरित क्रांति विस्तार योजना (BGREI) में गत वर्ष की तुलना में राज्य की राशि में बढ़ोतरी की गयी है।

किसानों के हित में राज्य बीज निगम कायम कर हर जिले में बीज ग्राम की स्थापना की जा रही है। बीज वितरण नीति लागू कर लैम्स एवं पैक्स के माध्यम से बीज सुलभ कराये जा रहे हैं। बीजों के समुचित उपचार की व्यवस्था शत प्रतिशत निश्चित करते हुऐ दलहनी फसलों में राईजोबियम कल्चर की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर भी कृषि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिया जा रहा है, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष यांत्रिकीकरण उप मिशन को भी शुरू किये जाने की सूचना दी गयी है, जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि दी जा चुकी है।

राज्य में १८३६ नये जन सेवक का चुनाव किया जा चुका है। साथ ही १४८८४ कृषक मित्रों के सहयोग से कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार में पर्याप्त मदद मिल रही है। आत्मा कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराकर पानी को बरबाद होने से बचाने में पूरी सहयोग कर रहा है।

इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि किसानों को खेती में हौसलाअफजाई हेतु इस शासन द्वारा बहुत से फैसले लिये गये हैं, कई क्षेत्रों में कार्य की शुरूआत की जा चुकी है और कई करने बाकी हैं। किसानों को बड़े पैमाने पर किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को अधिक-से-अधिक मिले, यह हमारी कोशिश है। इस निमित्त हमने विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी निदेश दिया है।

मैं कृषि विभागीय पदाधिकारियों से कहूँगा कि वे असली बीज, खाद एवं कीटनाशक सुनिश्चित कराएँ, जो वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध हों क्योंकि उत्पादन की रीढ़ यही है एवं किसान काफी ठगे जाते हरे हैं। मैं मुख्यालय स्तर से एवं Third Party inspection भी करवाऊँगा एवं जो पदाधिकारी इसमें असफल रहते हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई भी करूँगा। जो पदाधिकारी यह समझते हैं कि खेती का सारा दारोमदार किसार और भगवान पर है, वे यह भूल रहे हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र में काफी बड़ा निवेश कर रही है एवं इतनी बड़ी आबादी के जुड़े होने के कारण सरकार की भारी जिम्मेवारी बनती है।

कृषि प्रसार सेवाएँ ठीक से कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाय। Irrigation Department के साथ ठीक से Liaison हो। पदाधिकारी Field में रहें। प्रत्येक किसान अपने जनसेवक एवं कृषि प्रसार पदाधिकारी को जाने, यह वास्तव में उनके किसानों से निरंतर सम्पर्क की सफलता की पहचान होगी। मैं सभी पदाधिकारियों से कहूँगा कि वे इस टेस्ट को अपनायें।

मुझे उम्मीद है कि हमारे सूबे के किसानों की अधिक-से-अधिक तरक्की होगी और अनाज के पैदावार के मामले में न केवल आत्मनिर्भर होंगे बल्कि हम निर्यात करने में भी सक्षम होंगे।

जय हिन्द ! जय झारखण्ड !